भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1167

उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

सोमवार, 6 श्रावण, 1947 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकन, नियोजन और प्रतिधारण

1167. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

श्री के. सुधाकरन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2021-22 से अब तक वर्ष-वार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल कितने अभ्यर्थी नामांकित, प्रमाणित और नियोजित हुए है;

(ख) औपचारिक क्षेत्र में नियोजित अभ्यर्थियों सहित प्रमाणन के तीन महीने के भीतर कितने अभ्यर्थियों को मजदूरी आधारित रोजगार प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या सरकार नौकरी प्रतिधारण दरों और नियोजन-पश्चात औसत आय संबंधी आंकड़ा रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षु संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करना है।

वित्त वर्ष 2021-22 से एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

योजना	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
पीएमकेवीवाई	6,16,040	2,11,170	5,39,340	20,34,686
जेएसएस	4,61,996	7,26,284	5,07,337	4,55,856
एनएपीएस	5,90,785	7,38,252	9,32,731	9,85,641
सीटीएस	12,25,851	12,51,181	14,45,362	13,09,640

टिप्पणी: *एनएपीएस के तहत डेटा कार्यरत शिक्षुओं के लिए है और सीटीएस में डेटा सत्र 2021-2024 के लिए नामांकित उम्मीदवारों का है ।*

एमएसडीई की योजनाओं में, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों, अर्थात पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत प्लेसमेंट पर नज़र रखी गई। पीएमकेवीवाई के इन तीन संस्करणों में देश भर में 24,37,887 उम्मीदवारों को नियोजित किया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे विभिन्न आईटी उपकरण में भी यह अवसर प्रदान किया जाता है।

एमएसडीई की योजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में उनके सकारात्मक परिणाम को स्वीकार किया गया है और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में उनकी सफलता का उल्लेख किया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

पीएमकेवीवाई: एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर, 2020 में किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक आधार पर नियुक्त और आरपीएल घटक के तहत अभिविन्यसित 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को अधिक वेतन मिला या उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें अपने अप्रमाणित समकक्षी की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

जेएसएस: वर्ष 2020 में जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है या वे स्वरोजगार कर रहे हैं। 79% महिला प्रतिनिधित्व, 50.5% ग्रामीण हिस्सेदारी, बेहतर आजीविका के लिए रोजगार में बदलाव 73.4%, प्रत्येक लाभार्थी की औसत आय में 89.1% परवर्तन, जेएसएस द्वारा लाभार्थियों को संगठित करना 85.7% आदि को ध्यान

में रखते हुए, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षणार्थियों ने व्यावसायिक परिवर्तन किए हैं। अध्ययन ने यह भी पुष्टि की कि योजना में कौशलीकरण का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण करने वालों में से 63.5% को रोजगार मिला (वैतनिक+ स्व रोजगार, जिनमें से 6.7% स्व-नियोजित हैं)।

एनएपीएस: वर्ष 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की रोज़गार क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है और विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में अंतरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति को अपनाया गया है क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

*****